ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1985 के सर्वेक्षण में पता लगाए गए 4911 समस्याग्रस्त गांवों में से 4902 गांवों में 31.3.1994 तक स्वच्छ पेयजल के एक या अधिक स्रोत उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष 9 समस्याग्रस्त गांवों को 1994–95 के अंत तक कवर कर लिये जाने की सम्भावना है।

(ग) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की गई और संस्वीकृत योजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	संख्या
1985–86	124
1986–87	1105
1987–88	356
1988–89	786
1989–90	181
कुल :	2552

(घ) 1992–93 और 1993–94 में 914 गांवों की कवर किया गया है। 1994–95 में 500 गांवों को कवर किए जाने की सम्भावना है। 1995–96 और 1996–97 में कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या का निर्णय इन वर्षों के लिये वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निधियों के परिव्यय के अनुसार लिया जाएगा। राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के लिए आबंटन 27813 लाख रुपये है। गुजरात के लिये 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के लिये केन्द्रीय सहायता का आबंटन 7328 लाख रुपए है। आठवां पचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के आबंटन पर संबंधित वर्षों में निर्णय लिया जाएगा। इस पर अग्रिम रूप से निर्णय नहीं लिया जाता है।

(ङ) गुजरात में 1993–94 के लिये स्वच्छ पेयजल की सुविधा वाली ग्रामीण जनसंख्या की कवरेज हेतु लक्ष्य 6.300 लाख था जिसमें 1.058 लाख अनुसूचित जाति और 0.630 लाख अनुसूचित जनजाति के थे। 500 गांवों को कवर करने का लक्ष्य था। 1993–94 के दौरान इस प्रयोजन हेतु त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि 26.56 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि 56.21 करोड़ रुपये थी।

गुजरात में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

493. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु आवंटित की गई धनराशि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या-क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों की समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) गुजरात राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण

रोजगार, ग्रामीण जल सप्लाई, स्वच्छता और ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं–(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3)त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (4) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और (6) मरुभूमि विकास कार्यक्रम । गत 3 वर्षों अर्थात् 1991–92, 1992–93 1993–94 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित राशि के वर्षवार और जिलावार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं । [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 11]

(ख) से (घ) उपरोक्त कार्यक्रमों की निम्नलिखित की मार्फत नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है–(1) आवधिक प्रगति रिपोर्टें/वितरणियां (2) वित्तीय विवरणियां/आडिट रिपोर्ट (3) गहन फील्ड निरीक्षण और (4) समितियों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा । इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "क्षेत्र अधिकारियों" की एक योजना भी लागू की है जो प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी करती है जिसमें कार्यों की गुणवत्ता समय-सारणी और भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों को सही उपलब्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जाते हैं । समीक्षा रिपोर्टों और इन मूल्यांकनों अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ताकि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाया जा सके । उदाहरण के तौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में सभी राज्यों में (क) 210 जिलों में परिवार ऋण योजना लागू की है (ख) प्रति परिवार सहायता को बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपए कर दिया गया है और (ग) कार्यक्रम के अंतर्गत धंधे को सुदृढ़ बनाने के संशोधित मानदण्ड लागू किए हैं ।

Review of the IRDP

494. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have studied the review of the IRDP published by the review of the IRDP published by the ILO and if so, what are the salient points made in the review; and

(b) whether Government have on their own done any monitoring regarding the success of the programme and if so, to what extent this has helped the rural people and what percentage of funds has gone was to and if not, whether Government will now conduct investigations to stramline the programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL). (a) The report entitled India Employment, poverty and economic policies published by International Labour Organisation (ILO) dealt with the review of Integrated Rural Development Programme (IRDP) also. It has highlighted the important role played by the programme in reducing both the under employment and poevrty. Report also adocates increased budgetary allocation for programme. It also points out that administrative costs involved for the implementation of anti-poverty programmes are high and expects that role of Panchayati Raj Institutions for implementing such programmess will help reducing the administrative cost. It also mentions weak post assistanle support and lack of infrastructural factlities.

Government of India had stepped up the allocation of Ministry of Rural Development almost three times for the VIII Five Year Plan so that anti-povarty programmes could be persued vigorously. The involvement of Panchayati Raj Institutions and Non-Government organisations at grass root level has also been strongly emphassised. Allocation for developing infrastructure